प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निबन्धक, लोक सेवा अधिकरण, 25-ए, फेज-2 बसन्त बिहार, देहरादून

न्याय अनुमाग-1

देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2008

विषय- उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण हेतु सृजित 03 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना । महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या— 42/xxxvi(1)—एक/2007—326/2001 दिनांक 27 फरवरी, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—12—एक(4)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004 दिनांक 6—8—2004 द्वारा सृजित वाहन चालक का 01 पद एवं शासनादेश संख्या— 65—एक(4)/छत्तीस(1)/05—326/01 दिनांक 28—11—2005 द्वारा सृजित वरिष्ठ लिपिक के 02 पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांए, दिनांक 1—3—2008 से 28—2—2009 तक बढ़ायें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

- 2— उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008—2009 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या— 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2014—न्याय प्रशासन—00—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—04 लोक सेवा अधिकरण—00'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या— ए—1—1270 / 76—दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या— ए—2—877 / दस—92—24(8) / 92 दिनांक 7—11—92, (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय, ( आर०डी०पालीवाल) सचिव,

संख्या- 43 (V / xxxvi(1)एक / 08-326 / 2001 समदिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

( आलोक कुमार वर्मा)

nirantrata